



# आज हमारा



चौपाल से  
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 31 मार्च - 6 अप्रैल 2025 वर्ष-10, अंक-50

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुंरेना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

-पशुपालन विभाग की सब्सिडी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, सीएम बोले- आमदनी का साधन भी मिलेगा

## कुपोषण रोकने आदिवासियों को दुधारू गाय देगी सरकार

भोपाल। जगत गांव हमार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कुपोषित महिलाओं और बच्चों वाले परिवारों को दुधारू गाय देने का फैसला किया है। इसके साथ ही टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, सामुदायिक भवन निर्माण और हर घर तक बिजली-पानी पहुंचाने जैसी योजनाएं के लिए भी फैसले किए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार ने उन आदिवासी परिवारों की पहचान करने का निर्णय लिया है, जहां महिला और बच्चा कुपोषित हैं। ऐसे परिवारों को दुधारू गाय दी जाएगी, जिससे उन्हें पोषण के साथ-साथ आमदनी का भी साधन मिल सके। इस योजना को पशुपालन विभाग की सब्सिडी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

सब्सिडी पर गाय, भैंस

सीएम ने कहा कि आदिवासी परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए उन परिवारों को चिह्नित किया जाए, जिनके घर का बच्चा कुपोषित है और माता भी कमजोर है। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी पर गाय, भैंस और बकरी पालन की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है, और इसी के तहत यह योजना लागू की जाएगी।

इसलिए यहां होगा फोकस

गांवों में आदिवासी परिवार अमर्तौर पर मजरे-टोलों में बसते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आदिवासी गांवों, बलाहटों और मजरे-टोलों में आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भी कार्य किए जाएंगे।



**टिकाऊ फसलों वाली खेती** | मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय गांवों में टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। भूमि के अनुरूप फसलों का चयन करके के लिए भिन्नी का परीक्षण किया जाए और किसानों को बताया जाए कि कौन-सी फसल उनके लिए अधिक लाभकारी होगी। इसके अलावा, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।

मोटे अनाज की खरीदी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासी गांवों में पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और बैठकों के आयोजन के लिए सामुदायिक भवन बनाए जाएं। उन्होंने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 11,377 चयनित आदिवासी गांवों में उगाई जाने वाली रागी, कोफे-चूटकी जैसे मोटे अनाज (मिनेटन) की सरकारी खरीद के निर्देश भी दिए।

विशेष मंडियां शुरू कराएं

सीएम ने विशेष मंडियां शुरू करने को कहा गया, ताकि गांव के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और बिचौलियों का दखल समान हो। मछली पालन से आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में भी कार्य किया जाए। गिन स्थानों पर खेती की संभावना कम है, यहां पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए।

प्रदेश में खुलेगी देश की दूसरी फ्रूट वेजिटेबल लैब

## फल-सब्जियों में कीटनाशक के स्तर की होगी जांच, रिसर्च-स्टडी कर सकेंगे छात्र

ग्वालियर। जगत गांव हमार

ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खंडवा में अब करीब पौने तीन करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रदेश की पहली पेस्टीसाइड रेसिड्यू लैब तैयार की जा रही है। जहां फल-सब्जियों में कीटनाशक उपयोग के स्तर की जांच होगी। इसके जरिये भविष्य की योजनाएं भी वैज्ञानिक तैयार करेंगे। इस लैब के लिए प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया है। देश प्रदेश में सब्जियों-फलों के रकबे के साथ उत्पादन बढ़ा है। इसके पीछे बड़ी वजह फल-सब्जियों में कीटनाशक का ज्यादा उपयोग किया जाना भी है। ज्यादा उत्पादन से किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा कीटनाशक के उपयोग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी पैदा पसर रही हैं। ऐसे में फल-सब्जी उत्पादन में बढ़ रहे कीटनाशक के स्तर का आंकलन करने के साथ ही उससे होने वाले नुकसान को पहचानने के लिए फ्रूट वेजिटेबल कीटनाशक अवशेष लैब का निर्माण शुरू हो गया है।

**कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग-** कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अरविंद शुक्ला ने बताया कि, भारत में अब सब्जियों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक मात्र में होने लगा है। खासकर मिर्च वर्ग की फसलों में जिनमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च इसकी अन्य वैरायटों में इनके साथ ही फूलगोभी, कुकरबीटस सबसे अधिक पेस्टीसाइड का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इनमें बहुत सारे कीट लगने की संभावना रहती है। जिसके चलते किसान अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग करते हैं।



कृषि कॉलेज में होगी लैब

पेस्टीसाइड का उपयोग खाने में बहुत ही नुकसानदायक है। ऐसे में जानबूझकर जरूरी है कि, फसल पर पेस्टीसाइड का कितना लोड होना चाहिए, जो खरीद को नुकसान ना पहुंचाए, इसका लेवल मापने के लिए, अगर फसल में पेस्टीसाइड डाला गया है, तो उसके फल में कितना ऑब्जर्व हुआ। यह जानने के लिए खंडवा कृषि कॉलेज में पेस्टीसाइड रेसिड्यू लैब तैयार की जा रही है। जितने मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है।

फसलों पर शोध करेंगे वैज्ञानिक

इस लैब के स्थापित होने से खंडवा में अलग-अलग सब्सिडी फ्रिंजमें मिर्च, फूलगोभी, टमाटर और कुकरबीट पर शोध किया जा सकेगा कि, इनमें कितना पेस्टीसाइड फलों में पहुंच रहा है। कहीं वह स्वास्थ्य के नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। साथ ही यह भी एक शोध का विषय है कि, जो खेत में फसल पर कीटनाशक डाले जाते हैं या पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। वह किस तरह उसके फल और बीज में ट्रान्सफर होता है। यह पता लगाने में यह लैब मददगार बनेगी।

दो प्रकार की टैस्टिंग होगी

- कृषि वैज्ञानिक शोध से संबंधित टैस्टिंग करेंगे
- कृषि वैज्ञानिक विभिन्न रसायनों के जरिए टैस्टिंग करेंगे
- किसान फसल में पेस्टीसाइड लोड टेस्ट करा सकेंगे
- किसानों को कुछ तय फीस टैस्टिंग के लिए देनी होगी

तीन करोड़ की लागत से बनेगी लैब

लगभग तीन करोड़ की लागत से बनने जा रही यह अत्याधुनिक लैब प्रदेश की पहली और देश की दूसरी लैब होगी। अभी सिर्फ गुजरात के आनंद कृषि विश्वविद्यालय में यह लैब है। इस लैब में 5 एकसप्ट काम करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में दो एकसप्ट वैज्ञानिकों की नियुक्ति कर दी गई है। भविष्य में तीन अन्य वैज्ञानिक नियुक्त किए जाएंगे। सबसे पहले सब्जी मंडियों से सैंपल लेकर उन पर रिसर्च और टैस्टिंग की जाएगी।

लैब से रिसर्च और स्टडी कर सकेंगे छात्र

इनमें खास तौर से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक फास्फेट होते हैं। जिनका सीधा असर किडनी और लीवर पर पड़ता है। यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी कैम्पस और कॉलेज के स्टूडेंट इस लैब से रिसर्च और स्टडी कर सकते हैं। लैब के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से 2 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

-पर्यटन स्थल बैतूल को मिलेगी बड़ी सौगात

## बैतूल में बनेगा मध्यप्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व

-सतपुड़ा व मेलघाट के बीच बनाएगी सरकार

बैतूल। जगत गांव हमार

जिले में मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व (संरक्षण अभ्यारण्य) बनने जा रहा है। यह रिजर्व राज्य के वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कंजर्वेशन रिजर्व का उद्देश्य जैविक विविधता को बनाए रखना और वन्यजीवों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है। यह रिजर्व क्षेत्र वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा और साथ ही आसपास के समुदायों को भी वन्यजीवों से जुड़ी जागरूकता और स्थिरता के बारे में शिक्षा देगा। बैतूल जिले का यह कंजर्वेशन रिजर्व पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है, जिससे पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में बैतूल जिले

वन्यजीवों की रक्षा होगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह कंजर्वेशन रिजर्व लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें तासी रेंज और पश्चिम बैतूल वन मंडल के जंगल शामिल हैं। इस क्षेत्र में सासबहू नदी और बैतूल नदी बहती हैं, जो वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। रिजर्व के निर्माण से भारतीय गौर (बाइसन) जैसे वन्यजीवों की रक्षा होगी और पर्यावरणीय संतुलन में मदद मिलेगी।

में राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व (संरक्षण अभ्यारण्य) स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह रिजर्व सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच स्थित होगा, जिससे इन दोनों अभ्यारण्यों के बीच वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनेगा।

भरपूर मिलेगा रोजगार

इस परियोजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों के दर्शन का अवसर मिलेगा। स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना से वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही

# कृषक संगोष्ठी में बोलीं सांसद, प्राकृतिक कृषि से ही बचेगा खेती का भविष्य

लखर/भिंड। जागत गांव हमार

प्राकृतिक कृषि से ही खेती और किसानों का भविष्य बच पाना संभव है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही। इसे बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर आना होगा। यह विचार आज कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित कृषक संगोष्ठी 'भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक कृषि' विषय पर बोलते हुए इस भिंड दतिया क्षेत्र की माननीया सांसद संध्या राय द्वारा किसानों के बीच में व्यक्त किए गए।

कृषक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बतौर बोलते हुए सांसद संध्या राय ने कहा कि पुरातन काल से ही भारत में देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि किसानों द्वारा की जाती रही है। पिछले कुछ दशकों में खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति के साथ जमीन में पाए जाने वाले जीवाणु में भारी कमी देखी जा रही है। इसे बचाने के लिए किसानों को प्राकृतिक कृषि की ओर आना होगा। उन्होंने कहा आज प्रदूषण के चढ़ते दिल्ली जैसे शहर गैस चेंबर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन गांवों में आज भी हवा शुद्ध मिल रही है। किसानों को विचार करना होगा कि उनके बेटे शहरों में जाकर प्रॉब्लम नौकरी करें या खेती-पशुपालन के धंधे के रूप में अपनाये। इस अवसर पर सांसद द्वारा गोष्ठी में उपस्थित कई किसानों से खेती में किये जा रहे नवाचार पर उनके विचार जाने साथ ही उनसे खुलकर संवाद भी किया गया।



देसी गाय से तकनीक सीख आगे बढ़ सकते हैं किसान

उन्होंने कहा कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उन्नत तकनीकी अपना कर कृषि पशुपालन उद्योग की आदि क्षेत्रों में तकनीकी को सीख कर आगे बढ़े तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। संगोष्ठी में कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ही भारतीय देसी गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। वहीं एक देसी गाय से 30 पकड़ तक में खेती की जा सकती है। इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर भी प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर गिरवासा निकरा परियोजना अंतर्गत संचालित एससीपीएच प्रकल्प के तहत: गर्मियों में दूध बढ़ाने के लिए दिए गए विशेष का हितरण भी किया गया। संगोष्ठी में नवल मिश्रा द्वारा भी किसानों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के नवल मिश्रा, मनोज शर्मा, मयंक उद्दालिया, डीपी शर्मा, गंगा राम बघेल, शुभम कुशवाह, किरीत चंदेल, हिनोद दुबे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान महिलाएं भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में केंद्र वैज्ञानिक डॉ. के. वी. सिंह, डॉ. आरपीएस तोमर, डा. नरेंद्र भदौरिया, डॉ. रूपेंद्र कुमार, डॉ. बीपीएस रघुवंशी, परमेश सोनी, किशात प्रकाश, दीपेंद्र शर्मा आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. भानु प्रताप रघुवंशी द्वारा किया गया।

## देसी गाय के महत्व को समझे किसान

इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पुरातन भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ रही है। इसी कारण किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय संस्कृति में देशी भारतीय गाय का महत्व बहुत अधिक रहा है। यही कारण है कि पुरातन काल में कृषि और देसी गाय एक दूसरे की पूरक मानी जाती थी। लेकिन कालांतर में देसी गाय को भुला दिया गया आज खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के रूप में लागत बढ़ रही है। जबकि गाय का गोबर और मूत्र बहुत अच्छी खाद एवं कीटनाशकों का काम करता है। प्राकृतिक कृषि में देसी गाय का गोबर और मूत्र प्रयोग करके किसान पुनः खेती में लागत कम करने के साथ ही रोग और बीमारियों से भी बच सकते हैं। संगोष्ठी के माध्यम से भारतीय देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि के बारे में किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी गई।

9 को निकलेगी लॉटरी

# कृषि यंत्र अनुदान के लिए किसान अब 8 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किसानों को 8 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिनके विरुद्ध किसान 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद 9 अप्रैल के दिन लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

31 मार्च के दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा जारी किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए थे जिसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अब 8 अप्रैल 2025 कर दिया गया है, जिसके बाद लाभार्थी किसानों का चयन करने के लिए लॉटरी 9 अप्रैल 2025 के दिन निकाली जाएगी। कृषि उपकरण दरअसल कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न ट्रैक्टर चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसके लिए अब आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 8 अप्रैल 2025 कर दिया है। ऐसे में

## इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो इस प्रकार है:-  
बैकहो/ बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 HP ट्रैक्टर चालित), सब सॉइलर कृषि यंत्र, स्टील पीकर कृषि यंत्र, रेड बेंड प्लॉटर विश्व इनवलाइंड प्लेनट प्लॉटर एंड शेपर, फॉर रोडर/ ब्रूम रोडर, लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र, पट्टियाइजर बॉइकास्टर, प्लेयर/उजर (x HP तक)।  
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा? प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जल श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से थरोट रशिफ का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट जिले के सहायक कृषि यंत्रों के नाम से बकवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जिन भी किसानों ने अभी तक इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन नहीं किया है वे किसान 8 अप्रैल तक अपना आवेदन जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

# सफल किसान: सफलता की कहानी, सज्जन सिंह की जुबानी

- » डॉ. मुकेश कुमार भार्गव - वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान)
- » डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह
- » डॉ. अमृतलाल बसेड़िया
- » योगेश चन्द्र रिखाड़ी
- » डॉ. एबके कुशाहा
- » अरती बंसल
- » डॉ. पुनीत कुमार

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी (म.प्र.)

कहा जाता है कि जिसके पास जच्चा होता है वह पहाड़ से सोने को चीरकर अपना रास्ता बना लेता है। जहां युवा खेती से मुंह मोड़ते हैं। वहीं इनके बीच कुछ प्रगतिशील किसानों में ऐसे एक किसान हैं जो प्रेरणा लेकर आज प्रेरक बने हुए हैं। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिकों से कृषि तकनीकियों के अनुपालन के साथ अपनी मेहनत और लगन से आज खेती में लाभकारी परिणामों के साथ सफलता के मुकाम पर है। विगत 15 वर्ष पूर्व यह सामान्यतः परंपरागत खेती में सोयाबीन, गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि केवल एकल फसल के तौर पर ही करते थे। उन्हें खेती में कम लाभ और आय में निरंतरता नहीं मिलने से इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से कृषि तकनीकियों के द्वारा अपनी परंपरागत खेती में बदलाव किया जिसका विवरण इस प्रकार है।



विवरण  
नाम सज्जन सिंह मो. 96305 91917  
उम्र 48 वर्ष  
ग्राम किरौली  
विकासखण्ड एवं जिला शिवपुरी (म.प्र.) 473551  
कुल भूमि 25 एकड़  
प्रमुख फसलों की खेती टमाटर, शिमला मिर्च एवं बैंगन  
खरीफ रबी  
जायद गेहूँ, सरसों, गोभी एवं प्याज  
वर्ष भर में सभी फसलों की कुल औसत लागत व्यय खरबूजा, भिण्डी, खीरा  
वर्ष भर में सभी फसलों की कुल औसत आय रूप 70 लाख  
औसत शुद्ध आय समस्त फसलों से रूप 55 लाख  
लागत: लाभ अनुपात 1: 4.66  
पशुधन दो गाय एवं तीन भैंसों से 35 लीटर दूध उत्पादन जो रु 55 रूप प्रति लीटर के हिसाब से विक्रय हो जाता है।

1. नकदी फसलों में टमाटर मेढ़ पर ड्रिप, मल्टिचिंग सह स्ट्रिकिंग के साथ उत्पादन।
2. ड्रिप एवं मल्टिचिंग से शिमला मिर्च उत्पादन।
3. टमाटर के बाद खाली हुए खेतों में खरबूजा उत्पादन।
4. आधुनिक उपयोगी कृषि यंत्रों का प्रयोग इत्यादि प्रमुख है।

13 नई गतिविधियां  
डोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो उर्वरकों, जल विलेय उर्वरकों एवं अनुशंसित रसायनों का प्रयोग करने लगे हैं। जिसमें नीतेश शर्मा डोन पायलेट, आकाश चधरी, गौरव अवस्थी द्वारा कोरोमण्डल के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेवाएं भी दी जा रही हैं। सज्जन सिंह का मानना है कि आज का किसान यदि अपनी सूझबूझ एवं वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती करे तो यह व्यवसाय घाटे का नहीं हो सकता है और वह उत्तम खेती मध्यमबान जैसी पुरानी कहावत को चरितार्थ करता हुआ सफलता की नई ऊँचाई को छू सकता है। सज्जन सिंह अपनी जिदगी को बहुत ही खुशहाल अपने परिवार के साथ ही बिताए हैं और वनों के साथ उच्च शिक्षा कराते हुए संतुष्टि पूर्ण जीवन-यापन कर रहे हैं तथा खेती को अन्य प्रगतिशील किसानों से

मिलने वाली नई जानकारीयों तथा नये प्रयोगों को करना भी इनका शौक है। यह समय-समय पर कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी से प्रशिक्षण, प्रदर्शनों तथा उत्साह से कृषि तकनीकियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा एवं विश्लेषण कर अपनाने से साल दर



साल सफलता की नई ऊँचाई छू रहे हैं। ऐसे प्रेरक और जुनून वाले किसानों से कृषि में बदलाव कर दौर देखने को मिलता है। कृषि वैज्ञानिक भी इनके मेहनती और कृषि प्रति समर्पण के परिणाम को इनके खेतों में इनकी फसलों और इनको जो रहे लाभ से वैज्ञानिक और आधुनिक खेती की तकनीकियों के हस्तांतरण को सफल मानते हैं।

-सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया

# पीएसएस के तहत तुअर-उड़द, मसूर की खरीद को मंजूरी कृषि मंत्री शिवराज ने किसान हितैषी फैसला बताया

भोपाल। जागत गांव ह्वार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकारों से किसानों की कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे नहीं खरीदने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि फसलों का खरीद मूल्य से नीचे न जाए और इन खरीद में राज्य सरकारों से भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों को तूर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की अनुमति दी है, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से तूर दाल की खरीद का काम चल रहा है। चना, सरसों और मसूर दाल की खरीद पर शिवराज ने कहा कि इनकी खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा योजना) के माध्यम से की जाएगी।

## फसल खरीद के लिए राज्यों को मंजूरी

शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तूर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की अनुमति दे दी है। तूर दाल की खरीद का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मैं राज्यों से अपील करता हूँ कि वे एमएसपी पर खरीद की इस योजना को ठीक से लागू करें। पीएम आशा योजना के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद भी की जाएगी। हमने सरसों की खरीद के लिए अलग-अलग राज्यों को मंजूरी दी है। हमने तमिलनाडु में खोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी है।



## किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी खरीद एमएसपी मूल्यों से नीचे न हो। वहीं, राज्य सरकारों को इन खरीद में प्रभावी सहयोग करना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करना है और हम इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

शिवराज बोले-किसानों की समस्याओं को कांग्रेस ने नहीं समझा

## देश में अब तक 4.60 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी तैयार

जमीन बिक्री पर  
तत्काल किसान रजिस्ट्री  
में होगा अपडेट

-मंत्री ने कलेक्टरों को दिए जांच दल गठित करने के निर्देश

## 27.54 करोड़ तक पहुंचा धान खरीदी घोटाला, 7 एफआईआर

भोपाल। जागत गांव ह्वार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, पूर्व की सरकारों के समय का किसानों का दर्द प्रकट करते हुए कहा कि एक बहुत बड़े उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल थे, जिन्होंने राम दरबारी उपन्यास लिखा था. उसमें एक पात्र था किसान लंगड़। वो लंगड़ अपने खेत की नकल प्राप्त करने के लिए तहसील जाता है. एक नहीं अनेक दिनों तक वो एक अधिकारी के पास-फिर दूसरे अधिकारी के पास एक विभाग के पास-दूसरे विभाग के पास फिर तीसरे विभाग के पास भटकता रहता है और अंततः उसे नकल नहीं मिलती। उस लंगड़ की तकलीफ को कभी सामने वालों (विपक्ष) ने नहीं समझा. कांग्रेस ने आजादी के वर्षों बाद तक देश में शासन किया, लेकिन कभी किसानों की तकलीफ को नहीं समझा. इस तकलीफ को हमारे विजयनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और डिजिटल कृषि मिशन बनाकर का किसानों की सारी दिक्कतें समाप्त करने का फैसला किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसान रजिस्ट्री के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनके समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र कार्य करता है, जिसमें किसान मोबाइल या वेब एप्लिकेशन का उपयोग कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये क्रांतिकारी बदलकर रख देगा। अब तक 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बन चुकी है. किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं, गिरिराज के नाम है।



## किसान पहचान पत्र के रूप में सौगात

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के किसानों को किसान पहचान पत्र के रूप में बहुत उपयोगी सौगात दी है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण से कृषि के लाभ के सही वितरण में मदद मिलती है। इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि किसान ने कौन सी फसल बोई है। किसान रजिस्ट्री के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनके समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र कार्य करता है, जिसमें किसान मोबाइल या वेब एप्लिकेशन का उपयोग कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया-किसान रजिस्ट्री को राज्य में राजस्व रिकार्ड से जोड़ा गया है, जिससे तत्काल अपडेट हो सके, ताकि जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी रहे।

## हम जो कहते हैं, वो करते हैं

शिवराज सिंह ने कहा कि एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एक रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक किलो करते हैं और 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विवरण के कार्यक्रम में किसान सामने मोबाइल दिखाकर कहता है, पैसा खाते में आ गया। ये डिजिटल क्रांति के कारण संभव हुआ है। शिवराज सिंह ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी जी और एनडीए के नेतृत्व में भाजपा का मूलमंत्र है। लेकिन आजकल के राजनीतिक दल झूठे वादे कर, किसान, राज्य और जनता के साथ धोखा करते हैं।

## किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि डिजिटल योजनाएँ और किसानों के डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। डिजिटल क्रांति से सेवाओं में और योजनाओं का लाभ देने में तिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। किसानों का ये डाटा बिक्री डाटा है, जब तक किसान डाटा साइड करके के लिए अपनी रूढ़ि सहमति नहीं देता है, तब तक इसे साइड नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार निरंतर कई उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

भोपाल। खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान को लेकर हुई गड़बड़ी के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जांच दल गठित किया है। प्रदेश में धान खरीदी में अब तक 27 करोड़ 54 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। इसमें से 13.38 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष 14 करोड़ 16 लाख रुपए की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर जांच दल जिलों में खरीदी केन्द्रों से दी गई धान की सत्यापन रिपोर्ट एवं अन्य शिकायतों की जांच करेगा। खरीदी गई धान के मामले में हुई गड़बड़ी पर प्रदेश में अब तक सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। जबलपुर जिले में 5, रीवा और महर जिले में 1-1 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंत्री राजपूत ने कलेक्टरों को 7 दिन में विस्तृत जांच करार रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। टीम में उनके द्वारा तय किए गए अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर शामिल होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक या खाद्य अधिकारी इस जांच दल के संयोजक होंगे। उप आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कांफिडेंस और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कांफिडेंस इस जांच टीम के सदस्य होंगे।



## खाद्य मंत्री ने दिए ये निर्देश

- » खरीदी गोदाओं में कम मात्रा में धान जमा होने के कारणों की जांच कराई जाए।
- » संबंधित खरीदी केन्द्र, परिवहनकर्ता से शॉर्टेज की वसूली कर संबंधित किसानों को भुगतान किया जाए।
- » शॉर्टेज की भरपाई बाजार एवं अन्य माध्यमों से नहीं कराई जाए।
- » सीएसएमएस पोर्टल पर धान परिवहन करने वाले वाहनों, परिवहन की तारीख एवं मात्रा की जानकारी उपलब्ध है। इससे वाहनों का विवरण प्राप्त किया जाए।
- » जिलों एवं टोल नाकों से धान परिवहन करने वाले वाहनों की ट्रेकिंग एवं डाटा प्राप्त करें।
- » आरटीओ से धान परिवहन करने वाले वाहनों की श्रेणी, प्रकार और लोडिंग क्षमता की जानकारी प्राप्त करें।
- » अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।
- » जांच के दौरान जिला प्रबंधक सिविल सप्लाइज कांफिडेंस द्वारा मिलर्स को धान के नए डिलीवरी ऑर्डर जारी नहीं करें।
- » जांच के बाद जो मिलर्स सही पाए जाएं सिर्फ उन्हें ही ऑर्डर दिए जाएंगे।

## इन बिंदुओं पर जांच करेगी टीम

- खरीदी गई धान की मात्रा
- धान खरीदी के बाद परिवहन
- धान जमा करने की कार्यवाही
- धान कमी की मात्रा
- मिलर्स को भुगतान की स्थिति
- मिल अनुसूच धान प्रदाय की मात्रा
- धान उठव की मात्रा
- मिल अनुसूच सीएसएमएस जमा मात्रा

# तरक्की के साथ फसलों से दोस्ती-खेतों से प्यार जरूरी

**डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह**  
—प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लखार (भिंड), मप्र

बात उन दिनों की है जब मैं एक सुदूर अंचल के गांव से किशोरवय उम्र में हाई स्कूल के बाद महानगर में पढ़ने के लिए आया था। जीवन में पहली बार गांव से सीधे निकलकर आगरा जैसे बड़े शहर में पढ़ने आने का मौका मिला था। हालांकि इससे पूर्व बचपन में शायद एक दो बार ही आगरा आना हुआ होगा। एक बात उस दौर में मेरे मन में हमेशा सबसे ज्यादा रह-रह कर विचार में आती थी वह यह कि शहर में लोगों के पास इतनी बड़ी-बड़ी आलीशान कोटियां और गाड़ियां हैं।

मन में विचार आता था कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। क्योंकि इनके पास तो खेत भी नहीं है जिसमें कुछ पैदा होता हो जिससे यह पैसा चले हो सके। जबकि हमारे यहाँ तो इतना सारा खेत है और उन खेतों में हर फसल पैदा होती है। इसके बावजूद भी हमें एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ रहा है आखिर हमारा मकान शहर में क्यों नहीं है। शहरों में बड़ी-बड़ी कोटियों में रहने वाले लोगों के पास जब एक भी बोधा खेत नहीं है तो उनके पास पैसा आखिर आता कहाँ से है। बालक मन में यह विचार बार-बार आता था। क्योंकि वह बालक मन सिर्फ यही जानता था कि खेतों से ही अनाज, फल-फूल, सब्जी, तिलहन, दलहन यहां तक कि दूध, दही, घी सब कुछ गावों में ही तो पैदा होता है। फिर यह शहर में रहने वाले एक विशेष वर्ग के लोग इतने पैसे वाले कैसे हैं। लेकिन धीरे-धीरे समय गुजरा और किशोरवय मन के विचारों की गुंथी अपने आप सुलझती हुई चली गई। जैसे-जैसे कक्षाएं और उम्र बढ़ी वैसे-वैसे चीजों को समझने की समझदारी भी विकसित होती चली गई।

हम सबने बचपन से ही सुना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को आत्मा गांवों में ही बसती है। भारत की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियाओं से होता हुआ ही निकलता है। बावजूद इसके भारत के विकास की यात्रा में कृषि विकास पिछड़ रहा है। आज खेती-किसानी लाभ का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बनती जा रही है। इसके पीछे अनेकों कारण उभरकर सामने आ रहे हैं। खेती पर आने वाली लागत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। कृषि निवेश महंगा होने के साथ ही फसलों पर लगने वाले रोग, बीमारियां और खरपतवार का प्रबंधन भी महंगा सौदा साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों का अभाव और उनकी बढ़ती कीमतें भी खेती में एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आ रही हैं।

खेतों में आज मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है जो कि निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। प्रमुखता से देखा जाए तो वह समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई कृषि जोत। जिस अनुपात में परिवार बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में कृषि योग्य भूमि घटने के साथ ही प्रति व्यक्ति कृषि जोत भी कम हो रही है। आज पूरे देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ी है। आंकड़ों पर गौर

फरमाएँ तो देश में 85 प्रतिशत से अधिक लघु और सीमांत किसान हैं। यह किसानों का एक ऐसा समूह है जो कि उन्नत कृषि तकनीकी और नवीनतम कृषि यंत्रों का प्रयोग अपने खेतों में करने की क्षमता नहीं रखता है। आखिरकार एक से लेकर दो और तीन एकड़ का किसान आर्थिक रूप से भी इन



तकनीकियों को अपनाने में सक्षम नहीं है। एक तरफलागत बढ़ रही है और किसान तकनीकी भी अपनाने की और उम्म्खु हा है। इसके इतर पूरे देश में मिट्टी की सेहत गड़बड़ा रही है। साल दर साल मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मिट्टी की सेहत खराब करने में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका भी कम नहीं रही है। रासायनिक उर्वरकों के आने के बाद किसानों द्वारा जैविक और कार्बनिक खादों को लगभग भुला ही दिया गया है। कम ही किसान अब खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद, हरी खाद आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके चलते भूमि में जीवाणुओं की मात्रा खत्म होती चली जा रही है और खेत रेत बन रहे हैं।

मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होने के साथ ही जमीन के अंदर वायु भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। फलस्वरूप फसलों की सिंचाई मांग भी बढ़ी है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के चलते खेतों में पाये जाने वाले प्राकृतिक रूप से केचुए अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। विस्टा को कुछ ही घंटे में खाकर मिट्टी बना देने वाला गुबरेला भी अब जमाने से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब जरूरत मिट्टी की सेहत को सुधारने की है। जब तक मिट्टी की सेहत नहीं सुधरेगी तब तक कृषि उत्पादन भी नहीं बढ़ पाएगा। एक तरफ मिट्टी की सेहत खराब है तो वहीं दूसरी तरफ

किसानों को उचित समय पर उन्नतशील बीज भी नहीं मिल पा रहे हैं। धीरे-धीरे किसान के हाथ से अपनी फसलों के बीज भी निकलते जा रहे हैं। गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर जैसे कुछ बीजों को छोड़ दे तो अधिकांश बीजों पर अब कर्पास का आधिपत्य होता चला जा रहा है। सरकारी संस्थाएं भी किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। इस वर्ष उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गेहूँ तक के बीज की भारी कमी देखी गई थी।

यह सब इस बात की ओर इंगित करता है कि किसान के हाथ से धीरे-धीरे ही सही परंतु उसका स्वयं का अपना बीज बैंक पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा है। विभिन्न खाद्यान्न, तिलहन, सब्जी फल-फूल आदि फसलों के बीजों में हाइब्रिड/इंजीनरिंग भी एक प्रमुख समस्या है। जिसके कारण किसान को बाजार से हर साल नया बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही हाल रह तो आने वाले ही कुछ ही वर्षों में किसान पूरी तरह से बीज को लेकर प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर होकर रह जाएंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीज जरूरी हैं, लेकिन किसान का अपना ही बीज खत्म हो जाए इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय कृषि के लिए यह स्थिति किसी भी दृष्टिकोण से सुखद नहीं कही जा सकती है।

इन सब बातों के पीछे सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी मिट्टी की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और अपने परंपरागत बीजों को संरक्षक नहीं रख पाएंगे तब तक खेती बना पाना मुश्किल होगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमें अपने मृदा स्वास्थ्य के साथ ही भूमि में जीवाणु और पोषक तत्वों को भी संरक्षित कर रखना होगा। इसके साथ ही हमें स्वयं के बीजों पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। तब कहीं जाकर हम खेती किसानों को बचा पाने में सफल हो पाएंगे।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आखिरकार हम कितनी भी शहरी संपन्नता क्यों ना बढ़ा लें। राष्ट्र कितनी भी आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक तरक्की क्यों न करले। लेकिन जब तक हमें अपने अनाज, फल, सब्जी, तिलहन, दलहन, दूध, दही, मांस, अंडा आदि पैदा तो खेतों और किसानों के माध्यम से ही होगा। इसलिए बालक मन में जो विचार मेरे मन में बच-बाच आता था आज की मेरी परिपक्व समझ यह कहती है कि उसका कोई विकल्प न कल था, ना आज भी हमारे पास है और न आने वाले भविष्य में हमारे पास होगा। क्योंकि आखिरकार भोजन तो हमें खेतों से ही मिल पाएगा। इसके लिए हमें अपनी फसलों से दोस्ती और खेतों से प्यार करना ही होगा।

## जैव-संवर्धित किस्में: कृषि विकास और पोषण सुरक्षा के लिए एक स्थायी विकल्प

**डॉ. शालिनी चक्रवर्ती**  
—प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (मप्र)

कृषि और पोषण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, कृषि पोषिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है। अभी तक, वैज्ञानिकों का ध्यान मुख्य रूप से बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों के विकास पर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारा खाद्य उत्पादन 1950-51 में 5 करोड़ 10 लाख टन से बढ़कर आज लगभग 31 करोड़ टन तक पहुँच चुका है। घटती कृषि योग्य भूमि की बड़ी चुनौती के बावजूद भी भारत खाद्य अन्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थान प्राप्त किया।

कृषि के क्षेत्र में यह सब नये अनुसंधानों एवं नीतियों के कारण ही संभव हुआ। परन्तु कृषि के क्षेत्र में हुआ यह विकास हमको पोषण की दिशा में उतनी उन्नति नहीं करवा पाया जो कि अपेक्षित थी। कृषि के क्षेत्र में हुये इसमें बड़े बदलाव से लोगों के भोजन में कैलोरी उपलब्ध हुई परन्तु सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती चली गई। देश में प्रमुख फसलों का रकबा बढ़ा परन्तु फसलों का विविधीकरण कम होता चला गया। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में दैनिक आहार में उपस्थित पोषक तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं तथा पोषण विरोधी तत्वों की उपस्थिति स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कुपोषण दुनिया की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, जिसमें विकासशील देशों में 162 मिलियन से अधिक अविश्वसित बच्चे हैं। भारत में छिपी भूख से होने वाली बीमारियों का बोझ अपेक्षाकृत अधिक है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र विविध आहारों की सामर्थ्य की कमी के कारण पोषण संबंधी कमियों से सबसे अधिक ग्रस्त हैं।

**बायोफोर्टिफिकेशन की आवश्यकता:** बढ़ा हुआ कृषि का उत्पादन खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति का पूरक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1960 के दशक में हुई एक जांच में प्रति किलो चावल में आयरन की संद्रता 27.1 मिलीग्राम, लोहे की मात्रा 59.8 मिग्रा पाई गई। 2000 में ये मात्रा गिरकर प्रति किग्रा चावल में 20.6 मिग्रा और लोहे की मात्रा 43.1 मिग्रा हो गई। वहीं गेहूँ की किस्मों में प्रति किग्रा जिनक संद्रता 33.3 मिग्रा और लोहे की संद्रता 57.6 मिग्रा थी, 2010 में ये गिरकर प्रति किग्रा 23.5 मिग्रा (जिनक) और 46.4 मिग्रा (लोहा) हो गई। आयरन तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हार्मोनसोबिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी से मनुष्य में थकान, सांस लेने में तकलीफ नाड़ी की गति, सिर दर्द आदि समस्याएं होती हैं। बाजार में कृत्रिम रूप से तैयार किए गये पोषक तत्वों का लोग सेवन तो कर सकते हैं लेकिन महंगे होने के कारण सभी लोगों को यह उपलब्ध करना मुश्किल है। सभी लोगों को भोजन में सभी पोषक तत्व मिले इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्में विकसित की हैं। अपने देश में 16 फसलों की 85 बायोफोर्टिफाइड किस्में आज के समय में विकसित हो चुकी हैं जिनमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सावा, सरसों, मूंगफली, रतलू, अनार, आलू, फूलगोभी, मसूर,

शकरकंद, अलसी और गाजर की किस्में शामिल हैं। इन किस्मों में 15 सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाया गया है। इन किस्मों में प्रोटीन जिनक आयरन, कैल्शियम, विटामिन, विटामिन सी, अमोनिया, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व बढ़ाए गए हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 8 फसलों की 17 बायोफोर्टिफाइड किस्में राष्ट्र को समर्पित की थी। चावल-सीआर धान 315 जिनक से भरपूर होता है। गेहूँ-एक आई 1633 प्रोटीन, आयरन और जिनक से भरपूर होता है। मक्का-हाइब्रिड किस्में 1, 2 और 3 लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से भरपूर होती हैं। 'मधुवन गाजर' में -कैरोटीन और आयरन की उच्च मात्रा होती है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, सावा, में आयरन, जिनक और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया गया है।

बायोफोर्टिफाइड तकनीक को पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्में विकसित की हैं, ताकि लोगों को उनके आहार में सभी पोषक तत्व मिल सकें। ये फसलें, सूक्ष्म पोषक तत्व वाली फसल की किस्मों और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों को क्रॉस कराके उगाई जाती हैं। इसे जैव-संवर्धित यानी बायोफोर्टिफाइड किस्म कहा जाता है। इस तकनीक में आयरन, प्रोटीन, जिनक, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों की कमी वाली फसलों में प्लांटब्रीडिंग तकनीक से सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है।

**बायोफोर्टिफाइड के लाभ:** बायोफोर्टिफाइड फसले सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करती हैं, जिससे कुपोषण से जूझ रहे लोगों को लाभ होता है। ये फसलें आयरन, जिनक, विटामिन ए, विटामिन सी, और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। बायोफोर्टिफाइड लोगों को पोषण स्थिति में सुधार करने में लिए सम्मिलित किये गये कई अन्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों की तुलना में अधिक लाभप्रद है क्योंकि यह मुख्य भोजन के माध्यम से लोगों को लाभ करता है। कई कुत्रिम रूप से फोर्टिफाइड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शरीर लोगों को पहुँच से बाहर हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दैनिक आहार में उनका समावेश संभव नहीं है। बायोफोर्टिफिकेशन एक स्थायी विकल्प है क्योंकि एक बार जब फसल को पोषण संबंधी बेहतर विशेषता के साथ पैदा किया जाता है, तो उसके बीज और उत्पादों में वही जीनोटाइप होगा और चक्र जारी रहेगा।

## जलवायु संकट से मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ रहा है संकट

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में किशोरों में चिंता, असाद और निराशा का स्तर बहुत अधिक है। जबकि जलवायु परिवर्तन को अक्सर एक प्यावरणीय मुद्दे के रूप में देखा जाता है, यह शोध मानसिक स्वास्थ्य पर इसके गहरे प्रभाव को सामने लाता है, खासकर गरीब देशों में। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनगारकर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और प्रोबोप ग्लोबल के सहयोग से किए गए इस अध्ययन में जलवायु अनुकूलन के प्रयासों में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

जर्नल ऑफक्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ में प्रकाशित शोध में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन तीन प्रमुख रास्तों से किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है: पहला - घरेलू संसाधनों का नुकसान, दूसरा - भविष्य के बारे में अनिश्चितता और तीसरा - पारंपरिक तरीके से मुकाबला करने के तंत्र का टूटना। दक्षिणी मेडागास्कर में, जहां सूखे और रेत के तूफान आना आम बात हो गए हैं, युवा जीवित रहने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। अध्ययन में 83 किशोरों का सर्वेक्षण किया गया और मार्च 2024 में एक ग्रामीण जलाकों में 48 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। शोध के निष्कर्ष एक कठोर तस्वीर पेश करते हैं: पिछले साल 90 फीसदी घरों में भोजन खत्म हो गया था और 69 फीसदी किशोरों ने पूरा दिन बिना खाए गुजारा। शोध के दौरान एक किशोर ने बताया कि बहुत से लोग मर गए जिसमें कई बुजुर्ग भी शामिल थे, लेकिन वे कुपोषण के कारण मर गए। दूसरे ने बस इतना कहा, पानी नहीं है और जब सूखत लगी रहा होता है, तो हम पीड़ित होते हैं। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया कि विकासशील देशों में युवा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इस शोध में पाया गया है कि हमें यह भी विचार करने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि ये निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में युवाओं पर गौर किया जाएगा। शोध के मुताबिक, दक्षिणी मेडागास्कर में युवा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हैं। वे जलवायु परिवर्तन के किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। यह शोध यह स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है - यह एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है।

इस समय किसान मूंग की खेती करके इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं

**गर्मी के मौसम में मूंग की खेती के लिए अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए**

# गर्मी में मूंग की खेती: किसानों को मालामाल कर सकती हैं ये किस्में

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूँ की कटाई के बाद खाली खेत में किसान मूंग की बुवाई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। यह समय मूंग की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय प्राकृतिक आपदाओं जैसे-बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा आदि की संभावना कम रहती है। ऐसे में इस समय किसान मूंग की खेती करके इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की बाजार मांग होने से इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं।

**गर्मी में मूंग की खेती के लिए उन्नत किस्में:** गर्मी के मौसम में मूंग की खेती के लिए अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए ताकि कीट-रोग आदि का प्रकोप कम हो और उत्पादन भी अच्छा मिल सके। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई का उचित समय 10 अप्रैल तक होता है। जो किसान समय से मूंग की बुवाई करना करना चाहते हैं, वे 70 से 80 दिनों में तैयार होने वाली किस्मों का चयन कर सकते हैं। वहीं जहाँ किसान देरी से बुवाई कर रहे हैं उन किसानों को मूंग की 60-65 दिन में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। मूंग का बेहतर उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।

**पूसा 1431 किस्म:** मूंग की पूसा 1431 किस्म अधिक उपज देने वाली किस्म है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 12-14 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। यह किस्म पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके बीज बड़े, गोल और काले रंग के होते हैं। यह किस्म 56 से 66 दिन में पककर तैयार हो जाती है।



## पूसा 9531 किस्म

मूंग की पूसा 9531 किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म पीत धिरी रोग के प्रतिरोधी किस्म है और मध्य भारत के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 60 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म से औसत उपज 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त की जा सकती है।

## पूसा रत्न किस्म

मूंग की पूसा रत्न किस्म को आईएआर आई द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म पीला मोजेक वायरस के प्रति सहनशील है। मूंग की यह किस्म 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म से करीब 12 से 13 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। इस किस्म को पंजाब, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है।

## पूसा 672 किस्म

मूंग की पूसा 672 किस्म भी काफी अच्छी किस्म है, जो 60 से 80 दिन की अवधि में तैयार हो जाती है और बेहतर पैदावार देती है। इस किस्म से करीब 8 से 10 क्विंटल प्रति है। तक पैदावार हो सकती है। किसानों के लिए लाभदायी हो सकती है।

## पूसा विशाल किस्म

मूंग की पूसा विशाल किस्म को आईएआरआई की ओर से विकसित किया गया है। इसके बने ठोस और चमकदार होते हैं। मूंग की यह किस्म पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है। यह किस्म गर्मियों में 60-65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म से करीब 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

## केपीएम 409-4 (हीरा) किस्म

मूंग की केपीएम 409-4 (हीरा) किस्म को आईआईपीआर, कानपुर की ओर से विकसित किया गया है। यह एक बहुमुखी किस्म है जो खस-और ग्रीष्म दोनों मौसम में बेहतर पैदावार देती है। यह किस्म कई रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। ऐसे में इसमें रासायनिक उखरकों की बहुत कम जरूरत पड़ती है। मूंग की यह किस्म 65-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंग की इस किस्म से 8 से 10 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

## वसुधा (आई.पी.एम. 312-20) किस्म

मूंग की वसुधा (आई.पी.एम. 312-20) किस्म को आईआईपीआर कानपुर की ओर से विकसित किया गया है। यह किस्म सक्रोमोटा लीफस्पोट रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। यह किस्म 65 से 80 दिन में तैयार हो जाती है।

## सूर्या (आई.पी.एम. 512-1) किस्म

मूंग की सूर्या (आई.पी.एम. 512-1) किस्म को आईआईपीआर कानपुर द्वारा 2020 में जारी किया गया था। यह किस्म सक्रोमोटा लीफस्पोट और एन्थ्रेनोज रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। मूंग की यह किस्म 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म से करीब 12-13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। इस किस्म को विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त पाया गया है।

## कनिका (आई.पी.एम. 302-2) किस्म

मूंग की कनिका (आई.पी.एम. 302-2) किस्म को आईसीएआर-आईआईपीआर की ओर से विकसित किया गया है। यह किस्म पीला मोजेक रोग के लिए अधिक प्रतिरोधी है। इसके दाने बड़े आकारक हरे और चमकदार होते हैं। मूंग की इस किस्म से 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

## आईपीएम 205-7 (विराट) किस्म

मूंग की आईपीएम 205-7 (विराट) किस्म को आईआईपीआर कानपुर द्वारा 2014 में जारी किया गया था। यह किस्म पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। मूंग की इस किस्म से 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। यह किस्म 52 से 56 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म की फलियां लंबी, मोटी और चमकदार हरे रंग की होती हैं। यह किस्म पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु व कर्नाटक के लिए उपयुक्त मानी गई है।

## पूसा के बीज विक्रय केंद्रों से आनलाइन मगाएँ धान की उन्नत किस्मों के बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में बासमती धान की कुछ विशेष किस्में, किसानों में भारी मांग

## अतिरिक्त आमदनी के लिए गर्मी के सीजन में मक्का, भिण्डी और लोबिया की बुआई

भोपाल। जागत गांव हमार

साल 2024-25 के खरीफःसत्र में अब तक धान की बुवाई का रकबा 19.35 प्रतिशत बढ़कर 59.99 लाख हेक्टेयर हो गया है। भारत में हर साल धान की बुवाई लगभग 50 से 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। धान की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है और किसान इसकी अग्रेजी व उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसानों में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की मांग तेजी से बढ़ गई है। अब किसानों की गुणवत्ता वाले बीजों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के बीज केंद्रों से संपर्क कर आनलाइन बीज मंगा सकते हैं। और काफी किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। पूसा के बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित होते हैं, जो देश के सबसे प्रसिद्ध कृषि अनुसंधान संस्थानों में से एक है। वैज्ञानिक अनुसंधान और परीक्षणों के बाद इन बीजों को किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इनकी सफलता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। पूसा के बीज बेहतर उत्पादन, कम लागत और उच्च गुणवत्ता की फसल प्रदान करने में मदद करते हैं। पूसा द्वारा विकसित धान की किस्में ज्यादा पैदावार, कम पानी की आवश्यकता और कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस साल भी किसान बेहतर उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले चावल के लिए पूसा की उन्नत किस्मों को चुन रहे हैं।



## बासमती धान की इन किस्मों को किया सबसे ज्यादा पसंद

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में बासमती धान की कुछ विशेष किस्मों की भारी मांग देखी जा रही है। हाल ही में आयोजित किसान मेले के दौरान, 1.82 करोड़ रुपये के धान बीजों की बिक्री हुई। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी संख्या में किसानों ने बीजों की खरीदारी की है और खरीदारी का यह क्रम जारी है। डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार, किसान मेले के दौरान बासमती धान की निम्नलिखित किस्मों को किसानों ने सबसे ज्यादा पसंद किया :

पूसा बासमती	1509
पूसा बासमती	1121
पूसा बासमती	1718
पूसा बासमती	1847
पूसा बासमती	1985
पूसा बासमती	1979

इसके अलावा, हरियाणा के सिरसा और फतेहगढ़ जिलों के किसानों ने पूसा बासमती 1401 की सबसे अधिक खरीदारी की है।

## नॉन-बासमती धान की इन किस्मों की जबदस्त मांग

किसानों के बीच बासमती धान के अलावा, नॉन-बासमती धान की कुछ किस्मों का भी काफी मांग है। इनमें प्रमुख किस्में पूसा 2090 और पूसा 1824 रही। किसान अब धान की अग्रेजी किस्मों की तलाश कर रहे हैं ताकि कम मूल्य में अधिक मुनाफा कमा सकें।

## पूसा के बीज ऑनलाइन कैसे खरीदें

किसान भाई, अगर धान की खेती के लिए बासमती और नॉन बासमती किस्मों की बुआई करने की सोच रहे हैं तो वे अपने क्षेत्र के अनुसंधान पूसा के उन्नत बीज ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले IARI, पूसा की ऑनलाइन वेबसाइट [pusabeejari.res.in](http://pusabeejari.res.in) पर जाकर बीजों की ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। यहां आपको बीजों की होम डिलीवरी का विकल्प भी मिलेगा। होल डिलीवरी के लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऑनलाइन खरीदारी से किसान पूसा के प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज सीधे प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वम किस्मों को उच्च गुणवत्ता के बीजों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता का लाभ मिल सके।

भोपाल। जागत गांव हमार

गर्मी के सीजन में किसान विभिन्न फसलों की खेती कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में जो किसान गर्मी में मूंग, मक्का, भिंडी, लोबिया आदि फसलें लगाना चाहते हैं वे किसान गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा आदि की कटाई के तुरंत बाद पानी की पर्याप्त व्यवस्था होने पर बुआई के लिए खेत की तैयारी कर लें। सीहोर कृषि वैज्ञानिक के अनुसार ग्रीष्मकालीन मक्का, भिण्डी एवं लोबिया के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका पी.एच. मान 6 से 7 के बीच हो। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार एक बार मिट्टी पलतने वाले हल से जुताई करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर खेत की मिट्टी को भुरभुरी व महीन बना लें। किसान ग्रीष्मकालीन मक्का, भिंडी एवं लोबिया के बीज को भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए फफूंदनाशक दवा कार्बोण्डाजिम+ मैन्कोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें।

**कैसे करें मक्का की बुआई-** किसान गर्मी में मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मक्का की उन्नत किस्मों जैसे पीएमएच-7, पीएमएच-8, पीएमएच-10, कंचन, गौरव, विवेक मक्का, हाइब्रिड-27 आदि उपलब्ध किस्मों का चयन करें। किसान बुआई के लिए प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। सामान्यतः मक्का के लिए बीज दर 18 से 20 किग्रा व

## भिण्डी की बुआई कैसे करें

जो किसान अभी गर्मी में भिण्डी की खेती करना चाहते हैं वे किसान ग्रीष्मकालीन भिण्डी उन्नत किस्म पूसा सखली, पूसा मखमली, पखली गीत, इकॉन अनामिका आदि का चयन करें। किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में भिण्डी की बुआई के लिए 20 से 22 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेमी व पौध से पौध दूरी 20 सेमी रखें। अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन-रुख-पोटाश की मात्रा 40:50:60 किग्रा प्रति हेक्टेयर रखें। इसमें सुरुब व पोटाश की पूरी मात्रा व नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय एवं शेष नाइट्रोजन की मात्रा को दो भाग में दें।

## लोबिया की बुआई कैसे करें

ग्रीष्मकालीन लोबिया की खेती करने के लिए लोबिया की उन्नत किस्में जैसे पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, कशी गोरी, कशी करचल आदि का चयन करें। एक हेक्टेयर में लोबिया की खेती के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई के समय किसान कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेमी व पौध से पौध दूरी 10 सेमी रखें। अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन-रुख-पोटाश की मात्रा 20:60:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें।

संकर मक्का के लिए 12 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेमी एवं पौध से पौध की दूरी 30 सेमी रखें। अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन-रुख-पोटाश की मात्रा 120:60:40 किग्रा प्रति हेक्टेयर रखें। इसमें सुरुब व पोटाश की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय एवं शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को दो भाग में दें।

लक्ष्य खाद्यान्न की बर्बादी रोकना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाना

## किसानों के लिए खुशखबरी! अब हर गांव में बनेगा अनाज भंडारण केंद्र

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बताया जा रहा है। 31 मई 2023 को मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मकसद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए देश भर में गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सुविधाएं तैयार करना है।

**11 राज्यों में बन चुके हैं गोदाम:** इस योजना के तहत अब तक 11 राज्यों में 11 पैक्स के लिए गोदामों का निमाग्न पूरा हो चुका है। इनकी कुल भंडारण क्षमता 9,750 मीट्रिक टन है। महाराष्ट्र के अमरावती में 3,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला सबसे बड़ा गोदाम बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा और

राजस्थान में 250-250 मीट्रिक टन के छोटे गोदाम तैयार हुए हैं। अन्य राज्यों में भी 500 से 1,500 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाए गए हैं। इसके अलावा, 500 और पैक्स के लिए आधारशिला रखी जा चुकी है और कुल 575 पैक्स की पहचान की गई है।

इस योजना का लक्ष्य खाद्यान्न की बर्बादी रोकना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाना है। गोदामों के बनने से फसलों की आपात बिक्री पर रोक लग सकती है।

साथ ही, पैक्स को खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है, जिससे परिवहन लागत में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, योजना के असल प्रभाव को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यह अभी शुरूआती चरण में है।



### कर्नाटक में तेजी, बाकी राज्य पीछे

कर्नाटक ने इस दिशा में तेजी दिखाई है। राज्य में 2028-29 तक 218 पैक्स बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 128 पैक्स गठित हो चुके हैं। बीदर जिले के एकम्बा में 1,000 मीट्रिक टन का गोदाम भी तैयार हो गया है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में 258 और राजस्थान में 100 पैक्स की पहचान हुई है, लेकिन निर्माण कार्य की गति पर सवाल उठ रहे हैं।

### 2 लाख पैक्स का लक्ष्य

मंत्रालय ने देश की सभी पंचायतों और गांवों को जोड़ने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेपरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया, यह योजना किसानों के लिए विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रायोगिक परियोजना में मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योजना बड़े पैमाने पर लागू होने के बाद भी किसानों की सभी समस्याओं का हल कर पाएगी?

## ई-किसान उपज निधि (ई-केयूएन) पोर्टल किसानों के लिए आसान लोन का रास्ता

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

किसानों को उनकी फसल के बदले आसान और सस्ता कर्ज देने के लिए शुरू किया गया ई-किसान उपज निधि (ई-केयूएन) पोर्टल अब चर्चा में है। यह पोर्टल किसानों को आर्थिक तंगी से उबारने और साहूकारों के चंगुल से बचाने का एक जरिया बन सकता है। सरकार की इस पहल से किसानों को काफी सहूलियत मिल सकती है। आइए, जानते हैं कि यह पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं।



### कैसे मिलता है लोन?

**पंजीकरण:** किसानों को ई-केयूएन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है।

**उपज जमा करें:** अपनी फसल को नजदीकी मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में जमा करें।

**आवेदन:** पोर्टल पर लोन के लिए आवेदन करें, जो 26 जुड़े हुए बैंकों में से किसी एक के जरिए प्रोसेस होता है।

**लोन राशि:** फसल की कीमत के आधार पर कम ब्याज वाला कर्ज तुरंत मिलता है। इस पोर्टल से 26 बैंक जुड़े हैं, जिनमें 12 राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्राम बैंक शामिल हैं। ये बैंक मिलकर किसानों को लोन की सुविधा दे रहे हैं।

### जानिए किन राज्यों में कितना हुआ इस्तेमाल?

17 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान के 10, गुजरात के 5, मध्य प्रदेश के 2, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 1-1 किसान ने इस पोर्टल के जरिए लोन लिया है। कुल 19 किसानों ने अब तक इस सुविधा का लाभ उठाया है। हालांकि यह योजना किसानों के लिए मद्दतगार हो सकती है, लेकिन अभी तक केवल 19 किसानों ने इसका इस्तेमाल किया है। जानकारों का मानना है कि पोर्टल के बारे में जागरूकता की कमी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुंच सीमित होना इसके कम इस्तेमाल की बड़ी वजह हो सकता है।

### 19 किसानों को 21 लाख से ज्यादा का लोन

ई-किसान उपज निधि (ई-केयूएन) पोर्टल के जरिए 17 मार्च 2025 तक 19 किसानों को कुल 21,61,700 रुपये की ऋण राशि दी जा चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय उद्योगिता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री विश्वेन्द्र जयंतीभाई बांशिकिया ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। अभी तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है।

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नया नाम और लक्ष्य: अब पोषण पर भी फोकस

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कर दिया है। यह बदलाव साल 2024-25 के दौरान किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अब इस मिशन के जरिए देश में दाल, पोषक अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है।

लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मिशन के तहत किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें फसल उत्पादन और सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल, फसल प्रणाली पर आधारित प्रदर्शन, नए बीजों का उत्पादन और वितरण, पोषक तत्व व कीट प्रबंधन तकनीकें शामिल हैं।

इसके अलावा, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के जरिए किसानों को रिस्क डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक लिखित जवाब में दी।

उन्होंने बताया कि एनएफएसएनएम को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। वहीं, सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से फसले लेने की छूट भी दी है।

इस योजना में राज्य सरकारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएसएससी) की मंजूरी से मोटे अनाज और बाजार (श्री अन्न) को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, इस मिशन के असर को लेकर अभी ग्रांडड लेवल पर कितना बदलाव आएगा, यह देखना बाकी है।

मंत्रालय ने फिलहाल इसकी प्रगति या पिछले प्रदर्शन पर कोई आंकड़ा साझा नहीं किया। इस बदलाव से किसानों को कितना फायदा होगा और इसका असर खेती के तरीकों पर कैसे पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफहो पाएगा।



## दूध उत्पादन के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि, अब नया लक्ष्य तय

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

यह हमारे देश के लिए गौरव की ही बात होगी कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में हर दिन नये आयाम लिखे जा रहे हैं और यहां यह ही उल्लेखनीय है कि दुनिया के टॉप दूध उत्पादकों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। लिहाजा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आगामी पांच वर्षों में दूध उत्पादन को तीन सौ एमएमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है।

2014 में मिशन के शुभारंभ के बाद से, दूध उत्पादन में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसने अगले पांच सालों में 300 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो अभी 239 एमएमटी है, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री



राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया है, तब से देश में दूध

उत्पादन में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार को अगले तीन वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत की और वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया में

सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमने अगले पांच सालों में 239 एमएमटी से 300 एमएमटी दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

मंत्री ने कहा कि देश में करीब 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन में लगे हैं, जिनमें से 75 फीसदी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन को क्रियान्वित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण, गोजातीय आबादी का आनुवंशिक उन्नयन तथा गोजातीय पशुओं के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे किसानों के लिए दूध उत्पादन अधिक लाभकारी बन सके। 2014 में शुरू की गई यह योजना 2021-2022 से 2025-2026 तक विभाग की संशोधित पुनर्संयोजित योजनाओं के तहत जारी है।

-मृदा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टरेट की बैठक में लिए गए निर्णय

## पराली न जलाएं किसान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चलाएगा जागरूकता अभियान

भोपाल। जगत गांव हमार

प्रदेश में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के निदेशक मंडल की 169वाँ बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान एवं गेहूँ की कटाई के पश्चात जलने वाली पराली से होने वाले प्रदूषण पर गहन चर्चा हुई और इसके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने की।

प्रमुख सचिव कोठारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसान पराली न जलाएं इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।



बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने की। अभियान के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया।

### अप्रैल के प्रथम सप्ताह फिर बैठक

प्रमुख सचिव कोठारी ने पराली के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में स्थापित ताप नियंत्रण गृहों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिए हैं। बैठक में कटाई के बाद बचे बायोमास के वैकल्पिक उपयोग पर कर्तव्यता तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया।

### चार मोबाइल मॉनिटरिंग वैन

डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि वायु गुणवत्ता और अन्य प्रदूषकों की सतत निगरानी के लिए 4 सुसज्जित मोबाइल मॉनिटरिंग वैन स्थापित की जाएंगी। साथ ही, वायु गुणवत्ता सुचकक (एक्यूआई) 100 और उससे अधिक तक की धारिता तक स्थिति में तिन वनों में पड़चू गई है, वहां 99 बच वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता के सतत मापन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 92 करोड़ के बजट को स्वीकृत भी गई है।

बढ़ता तापमान सब्जियों एवं बागवानी फसलों के लिए बन सकता है समस्या

## फसलों को गर्मी के प्रकोप से बचाने कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की सलाह

भोपाल। जगत गांव हमार

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मौसम के तापमान से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में फसलों को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को गर्मी से फसलों के बचाव संबंधी सलाह जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों में भी तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। बढ़ता तापमान सब्जियों एवं बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में आप नए लगाए गए बागीचे में सिंचाई अवश्य करें। अधिक तापमान में टमाटर, मिर्च एवं बैंगन की फसलें खराब होने की आशंका रहती है। कृषि विशेषज्ञ डॉ. योगेश कुमार शर्मा के मुताबिक, बढ़ते तापमान से फसलों को बचाने के लिए 2 प्रतिशत नेपथलीन



एसिटिक एसिड (एनए) का घोल खड़ी फसलों पर छिड़काव करें ताकि फसलों का विकास अवरुद्ध न हो। अच्छे फल लगने के लिए फूल आने के दौरान सिंचाई से बचना चाहिए। आम में मिली बग और लीफ हॉपर की नियमित निगरानी करते रहें। इस मौसम में बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए प्रसिद्ध फसलें तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें।

यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कोटनाशक 48 ई.सी. मात्रा 1 मिली लीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। गेहूँ और जौ की फसलों की कटाई कर लें। भंडारण के लिए अनाज में नमी 12.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनाज का भंडारण में करने से पहले भंडार घर को अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े-कचरे को जला या दबा कर नष्ट कर दें। भंडारगृह की छत, दीवारों और फर्श पर एक भाग मेलाथियान 50 ई.सी. को 100 भाग पानी में मिला कर छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियाँ प्रयोग करनी पड़ें तो उन्हें एक भाग मेलाथियान व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगो कर छाया में सुखा लें।

## ग्यारह किसान मिलकर बनाएं समूह सरकार देगी 15 लाख रुपए तक लोन

भोपाल। जगत गांव हमार

केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें से एक ओर प्रमुख योजना है पीएम किसान एफपीओ योजना। दरअसल ये योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि संबंधित व्यापार करना चाहते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ग्यारह सदस्यों का समूह बनाना पड़ेगा और फिर 15 लाख रुपए बतौर लोन आर्थिक मदद ली जा सकती है। भारत में खेती-किसानी पर निर्भर आधे से ज्यादा आबादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेती में मौसम, पानी, बीज, मिट्टी आदि कई सारी समस्याएँ तो हैं ही। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना एक बड़ी समस्या है, जिसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार एक शानदार योजना लाई है। सरकार देश के किसानों के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना चला रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर

बनाना है। इसके तहत किसानों को कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार इस योजना के तहत 11 किसानों के समूह यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) को खेती-किसानी संबंधित तमाम बिजनेस सेटअप (एग्रीकल्चर बिजनेस) करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। इस योजना के माध्यम से सरकार किसान उत्पादक संगठनों की मदद से कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहती है। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए एक संगठन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। किसानों द्वारा बनाए गए इस संगठन में कम से कम 11 लोगों का होना अनिवार्य है। अगर आप भी केंद्र सरकार की एफपीओ योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। एफपीओ योजना में आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.enam.gov.in/web/> पर जाना होगा।

## बर्ड फ्लू पर एक नजर: संचरण, लक्षण एवं सुरक्षा उपाय

बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लूएंजा या पक्षी फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो इन्फ्लूएंजा ए वायरस के कारण होती है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है, लेकिन मानव और अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकती है। वायरस के विभिन्न उप-प्रकार हैं, जिनमें एच 5 एन 1 और एच 7 एन 9 सबसे अधिक चिंताजनक माने जाते हैं, क्योंकि वे मुर्गी के स्टॉक को नष्ट करने और मानव को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं।

**एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:** कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा और अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा। जबकि कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर पक्षियों में हल्के लक्षण पैदा करते हैं अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकते हैं। एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस से मानव में संक्रमित पक्षियों या दूधित वातावरण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने एच 5 एन 1 संक्रमण के कई मानव मामलों की रिपोर्ट की है, जिसमें उच्च मृत्यु दर है। स्थिति गंभीर है, हालांकि, मानव-से-मानव या बड़े पैमाने पर पशु-से-मानव संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, वायरस अपने भौगोलिक और जैविक मेजबान श्रृंखला का विस्तार कर रहा है।

**मेजबान श्रृंखला-** एवियन इन्फ्लूएंजा (एआई) वायरस विभिन्न प्रकार के मेजबानों को संक्रमित कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: पालतू पक्षी-मुर्गे, टर्की, बतख, गीजू,

क्रेल, फेजेंट, जंगली पक्षी- जलपक्षी (जैसे बतख, गीजू, हंस), तटीय पक्षी, शिकारी पक्षी (जैसे ईगल), प्रवासी पक्षी, स्तनधारी-मानव (कुछ उपप्रकारों से संक्रमित हो सकते हैं), बिल्ली, कुत्ता, बाघ, सूअर, घोड़ा।

**उपप्रकार और मेजबान श्रृंखला- एआई वायरस के विभिन्न उपप्रकारों में मेजबान श्रृंखला भिन्न होती है:**

**एच 5 एन 1:** मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव, बिल्ली, कुत्ते और अन्य स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है।

**एच 7 एन 9:** मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव को भी संक्रमित कर सकता है। एच 7 एन 2: मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव, सूअर और अन्य स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है।

**प्रसार- पक्षी फ्लू का प्रसार निम्न तरीकों से हो सकता है:** संक्रमित पक्षियों, उनके मल या दूधित सतहों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से, वायुजनित संचरण ध्वनन स्राव के माध्यम से, दूधित भोजन और पानी के माध्यम से, लक्षण: मानव एआई वायरस में विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा कर सकता है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं।

**यहाँ कुछ लक्षण दिए गए हैं:** हल्के लक्षण- बुखार (आमतौर पर उच्च), खांसी, गले में खराब, नाक से पानी आना या नाक बंद होना, सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, दस्त। **गंभीर लक्षण:** न्यूमोनिया, तीव्र ध्वनन संबंधी जटिलताएँ, ध्वनन विफलता, शॉक, मल्टी-ऑर्गन

विफलता, दौर, भ्रम या दिशाहीनता, गंभीर सिरदर्द या दर्द में जकड़न। **उच्च जोखिम वाले समूह:** कुछ समूह एआई से गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम में हैं, जिनमें शामिल हैं:- वृद्ध लोग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग (जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों की बीमारी), इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएँ लेने वाले)

**पक्षियों में - यहाँ कुछ लक्षण दिए गए हैं:** हल्के लक्षण - अस्वस्थता या उदासीनता, खाने की इच्छा में कमी, पानी की इच्छा में कमी, हल्का बुखार, खांसी या घरघराहट, नाक से पानी आना या नाक बंद होना, आंखों में पानी आना या आंखों का संक्रमण। **गंभीर लक्षण:** तीव्र बुखार, ध्वनन संबंधी जटिलताएँ (जैसे सांस लेने में कठिनाई), पाचन संबंधी जटिलताएँ (जैसे दस्त), तंत्रिका संबंधी जटिलताएँ (जैसे दौर), मृत्यु।

**अन्य लक्षण:** अंडे देने में कमी, अंडों का आकार या रंग में परिवर्तन, पंखों का गिरना या पंखों की स्थिति में परिवर्तन, त्वचा के रंग में परिवर्तन या त्वचा की स्थिति में परिवर्तन।

**उच्च जोखिम वाले पक्षी:** मुर्गे, बतख, गीजू, टर्की, प्रवासी पक्षी यदि आप अपने पक्षियों में इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। शीघ्र निदान और उपचार से पक्षियों की जान बचाई जा सकती है। **रोकथाम और नियंत्रण:** पक्षी फ्लू के प्रसार

के जोखिम को कम करने के लिए: बीमार या मृत पक्षियों के साथ निकट संपर्क से बचें पक्षियों या उनके वातावरण को संभालते समय सुरक्षात्मक गियर पहनें अच्छी स्वच्छता और बायोसिक्योरिटी उपायों का अभ्यास करें यदि आप पक्षियों के साथ काम करते हैं या संक्रमण के लिए उच्च जोखिम में हैं तो टीकाकरण करवाएं भारत सरकार ने एआई वायरस को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। ये उपाय भारत सरकार की एवियन फ्लू को नियंत्रित करने और मानव और पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

**एवियन इन्फ्लूएंजा (एआई) की रोकथाम के लिए अन्य सुरक्षा उपाय हैं:**

**व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय:** हाथों की स्वच्छता: एआई वायरस के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। **मास्क और दस्ताने:** एआई वायरस के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए।

**पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री मार्केट व घरेलू पक्षियों के मालिकों के लिए सुरक्षा उपाय:** पक्षियों की निगरानी: पक्षियों को निगरानी करें और किसी भी असामान्य लक्षण को सूचना तुरंत दें। **पक्षियों का टीकाकरण:** पक्षियों का टीकाकरण करवाएं। **पक्षियों के लिए स्वच्छ वातावरण:** पक्षियों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखें। **पक्षियों के बीच दूरी:** पक्षियों के बीच दूरी बनाए रखें। **पक्षियों के मल और मृत पक्षियों का निपटारा:** पक्षियों के मल और मृत पक्षियों का निपटारा सुरक्षित तरीके से करें।

- » डॉ. रश्मि कुलेश
- » डॉ. रणजित सिंह
- » डॉ. भावना गुप्ता
- » डॉ. ज्ञानमोहन सिंह थाकड़
- » डॉ. सुरभि नागर

- पशु जनस्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान एग्रीकल्चर एवं प्रशासन महाविद्यालय, नांदेदपिठि, जबलपुर (एम)

विभिन्न कम्पनियों और कृषि विभागों, युवा प्रगतिशील किसानों द्वारा करीब 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए

# मिलेट फूड फेस्टिवल कृषि मेले में मिलेट उत्पादों की रही धूम

जबलपुर। जागत गांव हमार

सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व नवीनतम कृषि तकनीक के प्रति जागरूकता के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में दो दिवसीय संभागीय मिलेट्स फेस्टिवल सह कृषि मेले का शुभारंभ शनिवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक रोहाणी तथा विशिष्ट अतिथि विधायक नीरज सिंह व संतोष बरकड़े थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनकेव्ही के कुलगुरु डॉ. पीके मिश्रा ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री रोहाणी ने मंच से कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से यह मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया है। केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ही मिलेट्स उत्पादक कृषकों के लिए काम कर रही हैं। साथ ही मिलेट्स उत्पादक कृषकों की आय बढ़ाने की दिशा में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार तेजी से किया जा रहा है। इस तरह के मेले उन युवाओं के लिए बेहतर मंच हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में मिलेट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि विभाग जबलपुर एसके निगम सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

## 200 से ज्यादा लगे स्टॉल

मेले में प्रदेशभर से आए विभिन्न कम्पनियों और कृषि विभागों, स्टार्टअप करने वाले युवा प्रगतिशील किसानों द्वारा करीब 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए। सबसे ज्यादा भीड़ कृषि यंत्रों और जैविक खाद की जानकारी देने वाले स्टॉलों में देखी गई।



फोटो: दीपक मिश्रा

## कृषकों ने जाना कृषि में क्या है नया

मेले में संभाग के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, पातालकोट के साथ प्रदेश के अन्य जिले सतना, मैहर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, सागर से भी किसान शामिल हुए।

## श्रीअन्न से हुई सजावट

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के प्रांगण में आयोजित मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र श्री अन्न से की गई सजावट रही। करीब 40 फीट के गोलाई में कृषि विभाग द्वारा श्रीअन्न से पेंटिंग और पुराने कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया।

## इन विभागों की भागीदारी

संयुक्त संचालक कृषि केएस नेताम ने बताया कि मेले में जेएनके विवि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, वन विभाग, दुग्ध संघ, मंडी बोर्ड, बीज निगम, एपीडीए, ऊर्जा विकास निगम, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, एसएचजी एवं एफपीओ सहित 46 विभागों की भागीदारी रही। उन्होंने बताया कि लघु धान्य फसलों को आमजनों की धाली तक पहुंचाने के लिए मेले में फ्रूट कोर्ट भी लगाया गया।

## नरसिंहपुर में खाक हो गई 25 एकड़ गेहूं की फसल

नरसिंहपुर। गर्मी बढ़ते ही आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ये किसानों के लिए बहुत ही कठिन समय में है, क्योंकि इस समय किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। ऐसे में जरा सी चिंगारी किसानों की सारी मेहनत आग में जलकर खाक हो सकती है। ताजा मामला नरसिंहपुर जिले में साली चौका क्षेत्र के ग्राम मारेगांव से सामने आया है। यहाँ गेहूं की खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लग गई।

## -लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी फसल जल गई

आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों के देखते ही देखते 25 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। मारेगांव में खेतों में लहलहा रही गेहूं की फसल अब जलकर खाक हो चुकी है। आग इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक खेतों में खड़ी फसल लपटों

की चपेट में आ चुकी थी। आग लगने की सूचना पर स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कई घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों को लाखों का नुकसान हो चुका था। गर्मी के मौसम में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल किसानों के लिए किसी बारूद से कम नहीं है। विजली के शॉर्ट सर्किट और अन्य कारणों से आए दिन आग लग रही है।

## जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं मालवा ज्योतिरियन फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)  
ईमेल- kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर, आनुवंशिकी एवं चाय प्रजनन विभाग सेम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेनलोलोनी एंड सासेस, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- gabriel.lal@shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. डा. बरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर डोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com, मोबा- 8210231304
4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कोके, राँची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. डा. देवेन्द्र पाटिल, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछवर, सिहोर (मप्र)  
ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएच, विश्वविद्यालय, सतना, मप्र  
ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. डा. विनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र  
ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिसर विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार।  
ईमेल- drksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उतराखण्ड।  
ईमेल- deepak.swcc.cot.gpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार।  
ईमेल- bharati.upadhyay@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. रोमा वर्मा, सक्नी विज्ञान विभाग महामा गांधी स्नातकी एवं वाणिज्यी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।  
ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

**जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...**

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आवाह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

**संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889**

**“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”**